



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110।

नई दिल्ली, बुधवार, मई 2, 2012/बैशाख 12, 1934

No. 110।

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 2, 2012/VAISAKHA 12, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2012

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित जिंक ऑक्साइड के आयातों के संबंध में आरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत।

सं. 15/14/2011-डीजीएडी.—यतः समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे एतदपश्चात पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) के अनुसार चीन जन.गण. (जिसे एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए चीन जन.गण. (जिसे एतदपश्चात सम्बद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित जिंक ऑक्साइड (जिसे एतदपश्चात सम्बद्ध वस्तु कहा गया है) के आयात पर दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 की अधिसूचना सं० 62/1/2000-डीजीएडी के तहत मूलतः निर्णायक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी और यतः केन्द्रीय सरकार ने अपनी दिनांक 02-11-2001 की अधिसूचना सं० 115/2001 सीमा शुल्क के तहत दिनांक 09.04.2001 से निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया था। यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) द्वारा

की गई सनसेट समीक्षा के आधार पर अपनी दिनांक 4 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना सं0 15/4/2005—डीजीएडी के तहत निर्णायक पाटनरोधी शुल्क लगाए रखने की सिफारिश की थी और यतः, केन्द्रीय सरकार ने सम्बद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करते हुए दिनांक 7 मई, 2007 की एक अधिसूचना सं0 64/2007-सीमा शुल्क जारी की थी।

2. यतः, सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार इस अधिरोपण की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि समाप्त होने की तारीख से अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क, यदि उनका पहले से प्रतिसंहरण नहीं किया गया तो, का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और उपर्युक्त नियम प्राधिकारी से पाटनरोधी शुल्क की अवधि बढ़ाने की जरूरत की समीक्षा करने की अपेक्षा करते हैं और प्राप्त जानकारी के आधार पर, यदि यह संतुष्टि हो जाती है कि ऐसे शुल्क का विस्तार करने के लिए पर्याप्त औचित्य है तो प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार से इसका विस्तार करने की सिफारिश कर सकते हैं। उपर्युक्त प्रावधान के अनुरूप मै0 ट्रान्सपेक सिलाक्स लिमिटेड और मै0 रुबामिन लिमिटेड ने चीन जन.गण. मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के कथित पाटन की निरन्तरता अथवा पुनरावृत्ति होने और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने का आरोप लगाते हुए संयुक्त रूप से विधिवत प्रमाणीकृत एक आवेदन दायर किया है और सम्बद्ध देश के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने, उसे निरन्तरता बनाए रखने और उसमें वृद्धि करने का अनुरोध किया है। यह याचिका प्राधिकारी द्वारा निर्धारित फार्म में और ढंग से की गई है तथा इसमें सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क की निरन्तरता बनाए रखने के लिए प्रथमदृष्टयां साक्ष्य मौजूद हैं।

घरेलू उद्योग

3. यह आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से मै0 ट्रान्सपेक सिलाक्स लिमिटेड और मै0 रुबामिन लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया है। पिछले निष्कर्षों में यह प्रेक्षण किया गया कि घरेलू उद्योग में भारी संख्या में एसएसआई इकाईयाँ हैं। विचाराधीन उत्पाद के भारत में लगभग एक सौ घरेलू उत्पादक हैं और उनमें से अधिकांश असंगठित सेक्टर में हैं। यह याचिका दो सबसे बड़े उत्पादकों द्वारा दायर की गई है जिनका व्यक्तिगत उत्पादन 25% से कम है परन्तु सामूहिक रूप से यह कुल भारतीय उत्पादन का लगभग 31% बनता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आवेदकों का सम्बद्ध वस्तु का भारतीय उत्पादन में एक प्रमुख हिस्सा बनता है और अतः नियमों के आशय के अन्तर्गत वे घरेलू उद्योग बनते हैं।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. मूल जाँच में अन्तर्गत उत्पाद 'जिंक ऑक्साइड' था। यह सनसेट समीक्षा होने के कारण, इस जाँच में वह उत्पाद शामिल होगा जो मूल जाँच और विगत के एसएआर जाँच में शामिल था। वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड एक सफद/ऑफ

व्हाइट पावडर है जिसका रासायनिक फार्मूला 'जेडएनओ' है। यह रेग्यूलर आईपी और फिड ग्रेड नामक तीन ग्रेडों में उत्पादित किया जाता है। रेग्यूलर ग्रेड में इसकी न्यूनतम शुद्धता 98% है जबकि आईपी में इसकी न्यूनतम शुद्धता 99% है। जिंक ऑक्साइड का प्रयोग ऑटोमोबाइल टायरों, रबड़ का सामान, सिरैमिक्स, उच्च शुद्धता वाले जिंक रसायनों जैसे सल्फेट क्लोराइड आदि का विनिर्माण करने में किया जाता है। यह सिरैमिक उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और यह पशु खाद्य निरूपण में एक संपूरक है। यह दो विभिन्न सीमा शुल्क वर्गीकरणों के अन्तर्गत आता है – जिंक ऑक्साइड सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 28 के उप शीर्षक 2817.0010 और अध्याय 38 (विविध रसायन उत्पाद) के उप शीर्षक 3812.3030 के अन्तर्गत वर्गीकृत अकार्बनिक रसायन है। तथापि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतक है और यह इस जाँच के दायरे में किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

सनसेट समीक्षा की शुरुआत

5. साक्ष्यों सहित विधिवत दायर आवेदन के मद्देनजर और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार प्राधिकारी सम्बद्ध वस्तु के संबंध में प्रभावी शुल्क के अधिरोपण की निरन्तरता बनाए रखने की जरूरत की समीक्षा करने और यह जाँच करने के लिए कि क्या इस शुल्क के समापन से पाटन की अवस्थिति बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, ऐतदङ्घारा सनसेट समीक्षा जाँच प्रारम्भ करते हैं।

शामिल देश

6. इस जाँच में शामिल देश चीन जन.गण. है।

जाँच अवधि

7. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 है। तथापि क्षति विश्लेषण में वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और जाँचावधि शामिल होगी। पाटन एवं क्षति की संभावना का निर्धारण करने के लिए जाँच की अवधि के पश्चात के आंकड़ों का परीक्षण भी किया जा सकता है।

प्रक्रिया

8. यह जाँच, यह निश्चित करेगी कि क्या उपाय के समापन से पाटन एवं क्षति की अवस्थिति बनी रहेगी या उसकी पुनरावृत्ति होगी। इस समीक्षा में दिनांक 4 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना सं 0 15/4/2005-डीजीएडी (एसएसआर जाँच के अन्तम निष्कर्ष) के सभी पहलू शामिल होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

9. सम्बद्ध देश से जात निर्यातकों और सम्बद्ध देश की सरकार को भारत स्थित उनके दूतावास के जरिए, भारत में इस उत्पाद से संबंधित जात आयातकों और उनके प्रयोक्ताओं को निर्धारित स्वरूप और ढंग से संगत जानकारी प्रस्तुत करने और अपने विचारों से अधोलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सम्बोधित किया जा रहा है:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य विभाग
कमरा सं0 240, उद्योग भवन,
नई दिल्ली-110107

10. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित ढंग से जाँच से संगत निवेदन कर सकता है।

समय सीमा

11. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु किया गया कोई भी अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए ताकि यह प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) से अनधिक समय के भीतर पहुँच जाना चाहिए। यदि निर्धारित समयावधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

12. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे प्रस्तुत मामले में अपने हित (हित की प्रवृत्ति सहित) के बारे में सूचित करें और अपनी-अपनी प्रश्नावलियों के प्रत्युत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने अथवा नहीं जारी रखने की आवश्यकता के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियाँ इस जाँच के शुरू होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के अन्दर प्रस्तुत करें।

गोपनीय आधार पर उत्तर प्रस्तुत करना

13. सभी हितबद्ध पक्षकार पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(1) के अनुसार प्रदत्त गोपनीय सूचना के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार एक गोपनीय तथा अगोपनीय सार प्रदान करेंगे। गोपनीय जानकारी का अगोपनीय पाठ या अगोपनीय सार पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे कि यह अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जानकारी की सार्थक समझ प्रदान करा सके। यदि जानकारी उपलब्ध कराने वाले पक्षकार के विचार से ऐसी जानकारी इस तरह की है कि उसका भाव, सार में व्यक्त नहीं किया जा सकता है तो उसके कारणों का विवरण देना अपेक्षित होगा। बिना चिन्ह के उपलब्ध कराई गई सूचना अगोपनीय मानी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी किसी भी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

14. उपर्युक्त पैरा में किसी बात के उल्लिखित होने के बावजूद यदि प्राधिकारी इस तथ्य से सन्तुष्ट हो जाते हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा सूचना का आपूर्तिकर्ता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या इसका सामान्यीकृत या सार रूप में प्रकटीकरण करने को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना को नजरअंदाज कर सकते हैं।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

15. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

16. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जाँच में बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

1595 41/12 - 2

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2012

(Sunset Review)

Subject : Sunset Review of anti-dumping duty imposed concerning imports of Zinc Oxide originating in or exported from China PR.

No. 15/14/2011-DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (herein after referred to as the AD Rules), definitive anti-dumping duty was originally recommended vide notification No.62/I/2000-DGAD dated 5th October, 2001 on import of 'Zinc Oxide' (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country) and whereas the central government imposes definitive anti-dumping duty w.e.f 09.04.2001 vide its notification no 115/2001-custom of 02.11.2001. Whereas upon a Sunset Review undertaken by the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), the Authority recommended continuation of definitive Anti-dumping duty vide its notification No.15/4/2005-DGAD dated 4th April, 2007 and whereas the Central Government issued its Notification No.64/2007-Customs dated 7th May, 2007 imposing anti-dumping duty on the subject goods.

2. WHEREAS in terms of the Customs Tariff (Amendment) Act 1995 the antidumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Rules supra require the Authority to review the need for extension of Anti Dumping Duty and if it is satisfied, on the basis of information received that there is sufficient justification for extension of such duty, the Authority may recommend to the Central Government for its extension. In terms of the above Provision, M/s Transpek Silox Limited and M/s Rubamin Limited have jointly filed a duly substantiated application alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from China PR and consequent injury to the domestic industry and have requested for review, continuation and enhancement of the anti-dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country. The petition is in the form and manner prescribed by the Authority and contains *prima facie* evidence for the continuation of anti-dumping duty on the subject goods from the subject country.

Domestic industry:

3. The application has been jointly filed by M/s Transpek Silox Limited and M/s Rubamin Limited on behalf of the domestic industry. It has been observed from the previous findings that the domestic industry comprises of large number of SSI units. There are about a hundred domestic producers of the product under consideration in India and most of them are in the

unorganized sector. The petition has been filed by two largest producers, whose individual production is below 25%, but collectively accounts for about 31% of Indian production. As per the information available, the applicants account for a major proportion in Indian production of the subject goods and therefore constitute the domestic industry within the meaning of the Rules.

Product under consideration and Like Article:

4. The product involved in the original investigation was 'Zinc Oxide'. This being a Sunset review, the investigation covers the product covered in the original investigation and the previous SSR investigation. The product under consideration in the present petition is Zinc Oxide. Zinc Oxide is a white/off white powder with chemical formula 'ZnO'. It is produced in three grades, namely regular, IP and feed grade. In regular grade, it has purity of minimum 98%, whereas in IP it has purity of minimum 99%. Zinc Oxide is used in the manufacture of automobile tyres, rubber goods, ceramics, high purity zinc chemicals, such as sulphate, chloride, etc. It is also used as a raw material in ceramic industry and a supplement in animal feed formulations. It is covered under two different customs classification - Zinc Oxide is an inorganic chemical classified under Chapter 28 under sub-heading 2817.0010 and Chapter 38 (Miscellaneous chemical products) under sub-heading 3812.3030 of the Customs Tariff Act. The customs classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

Initiation of Sunset Review:

5. In view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of the AD Rules, the Authority hereby initiates a Sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Country involved:

6. The country involved in this investigation is China PR.

Period of Investigation:

7. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is 1st April 2011 to 31st March 2012. However, injury analysis shall cover the years 2008-09, 2009-10, 2010-11 & POI. The data beyond POI may also be examined to determine the likelihood of dumping and injury.

Procedure:

8. The investigation will determine whether the expiry of the measure would likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The review covers all aspects of Notification No. 15/4/2005-DGAD dated 4th April, 2007 (final findings of the SSR investigation).

Submission of Information:

9. The known exporters in the subject country, the government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority,
Ministry of Commerce and Industry
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Department of Commerce
Room No.240, Udyog Bhawan,
New Delhi-110107.**

10. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit stated in this Notification.

Time Limit:

11. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

12. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the AD measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of information on confidential basis:

13. All interested parties shall provide a confidential and non-confidential summary in terms of Rule 7(2) of the AD Rules for the confidential information provided as per Rule 7(1) of the AD Rules. The non-confidential version or non-confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties. If in the opinion of the party providing information, such information is not susceptible to summary; a statement of reasons thereof is required to be provided. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information.

14. Notwithstanding anything contained in Para above, if the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

Inspection of public file:

15. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation:

16. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority